बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 159 ● नई दिल्ली ● बुधवार 08 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

### दिल्ली विधानसभा सुरक्षा में चूक - तीस हजारी कोर्ट का आदेश, आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी सरबजीत

नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में हुए सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी सरबजीत सिंह को तीस हजारी कोर्ट ने आठ दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। यह फैसला कोर्ट ने पुलिस की उस अर्जी पर सुनाया, जिसमें उन्होंने आरोपी से पूछताछ और मामले की तह तक जाने के लिए और अधिक समय मांगा था। दिल्ली विधानसभा सुरक्षा में चूक मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने अदालत में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने आरोपी सरबजीत की आठ दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है।

## पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे

नई दिल्ली । असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के तीन पासपोर्ट होने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद असम पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. असम पुलिस दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पहुंची. हालांकि वहां कांग्रेस प्रवक्ता नहीं मिले, जिसके बाद वो कुछ सामान अपने साथ लेकर गई है. असम पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, वह कल गुवाहाटी से भाग गए थे. मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पुलिस उनके दिल्ली स्थित आवास पर गई थी, लेकिन वह हैदराबाद भाग गए हैं. कानून अपना काम करेगा.

**पवन खेड़ा के घर पर रेड को लेकर भड़की कांग्रेस**

असम पुलिस की पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और डरे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह उचित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह की बदले की कार्रवाई है, एक दबंग जो राय मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबा रहा है, जो उसके कई काले कारनामों को उजागर कर रहा है. जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है. यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को आसन्न हार का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन अलग-अलग पासपोर्ट कैसे हैं? उनको तीन पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत है? क्या वे कोई अपराधी हैं? हिमंता बिस्वा सरमा के पास के भी एक से यादा पासपोर्ट मौजूद हैं? क्या वे असम चुनाव हारने के बाद कहीं भागने की तैयारी में हैं? उन्होंने कहा, हिमंता बिस्वा सरमा की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित है, लेकिन उनकी पत्नी दो मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हैं, कैसे? भारत के कानून के हिसाब से आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते तो क्या रिंकी भुइयां सरमा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? क्या देश के गृहमंत्री अमित शाह को ये जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी 3 पासपोर्ट रखती हैं? गृहमंत्री अमित शाह जवाब दें- क्या वो एसआईटी बिठाकर इस मामले की जांच कराएंगे?

## 16500 करोड़ के सरकारी ठेके, बहुजन समाज को कितना हिस्सा? राहुल बोले- सरकार के पास डाटा ही नहीं

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में सार्वजनिक निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकों में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों की हिस्सेदारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास इस बात का कोई डाटा ही नहीं है कि इन वर्गों को कितने ठेके दिए गए। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि उन्होंने पिछले साल दिए गए 16,500 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक निर्माण ठेकों में एससी/एसटी और ओबीसी उद्यमियों की भागीदारी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जवाब बेहद चिंताजनक था। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस संबंध में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। दरअसल, राहुल गांधी ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 6264 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से पिछले पांच वर्षों में दिए गए ठेकों की संख्या और कुल मूल्य की जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि इनमें से कितने ठेके एससी/एसटी और ओबीसी स्वामित्व वाले व्यवसायों को दिए गए और क्या सरकार ने एससी/एसटी उद्यमों के लिए तय चार प्रतिशत लक्ष्य को पूरा किया है। उन्होंने ओबीसी उद्यमियों के लिए भी ऐसे लक्ष्य तय करने की योजना पर सवाल उठाया। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राय मंत्री तोखन साहू ने बताया कि कुल ठेकों का डेटा तो उपलब्ध है, लेकिन एससी/एसटी और ओबीसी स्वामित्व वाले व्यवसायों को दिए गए ठेकों का कोई अलग ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्माण ठेकों के लिए ऐसी ट्रैकिंग अनिवार्य नहीं है। राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीति के मुताबिक लघु व मध्यम उद्यमों से कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद होनी चाहिए, जिसमें SC/ST स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए 4 प्रतिशत का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे बड़े और लाभदायक सार्वजनिक निर्माण ठेकों में इस नीति को लागू नहीं किया जाता। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बताया जो जानबूझकर सामाजिक और आर्थिक न्याय को कमजोर करता है। संसदीय आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण ठेकों की संख्या और उनका मूल्य लगातार बढ़ा है। सिर्फ 2025-26 में ही 8,402 ठेके दिए गए, जिनकी कुल कीमत 16,587 करोड़ रुपये रही।

## रविशंकर प्रसाद बोले- क्या मर्यादा भूली कांग्रेस, गुजरात का अपमान क्यों? खरगे के बयान पर किया पलटवार

नई दिल्ली । जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खरगे के कथित गुजरात के लोगों को अनपढ़ बताने वाले बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को शोभा नहीं देती। भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने इस टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया और कांग्रेस अध्यक्ष से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह मर्यादा भूल चुका है? प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या किसी राय के लोगों को इस तरह संबोधित करना उचित है। उन्होंने कहा क्या महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और विक्रम साराभाई जैसे महान व्यक्तित्व भी अनपढ़ थे? भाजपा सांसद ने आगे कहा कि गुजरात की साक्षरता दर लगभग 82 प्रतिशत है और इसमें पिछले वर्षों में सुधार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राजनीतिक विरोध के चलते कांग्रेस इस तरह के बयान दे रही है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख बताने की मांग की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सलाह दी कि वे इस बयान से खुद को अलग करें और पार्टी अध्यक्ष से माफी दिलवाएं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खरगे के अन्य बयान, जिनमें भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) पर की गई टिप्पणियां शामिल हैं, समाज में तनाव बढ़ाने वाली हैं। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केरल में एक बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे गुजरात या अन्य जगहों के अनपढ़ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल में ऐसा संभव नहीं है।

## दिल्ली में शुरू हुआ 12वां इंडिया रबर एक्सपो 2026, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित 12वें इंडिया रबर एक्सपो 2026 के उद्घाटन किया। इस चार दिन की प्रदर्शनी में देश-विदेश से कई प्रतिनिधियों आए। इस महाकुंभ को एशिया की सबसे बड़ी रबर प्रदर्शनी माना जा रहा है, जो भारतीय रबर क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी. IRE 2026 केवल घरेलू नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय मंच है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों ने भारत को एक सशक्त विनिर्माण राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है. उन्होंने बताया कि रबर उद्योग इस बढ़ती औद्योगिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभर रहा है.मुख्यमंत्री ने कहा, रबर उद्योग को देश की औद्योगिक प्रगति का एक अपरिहार्य स्तंभ बताया, जो ऑटोमोबाइल से लेकर एयरोस्पेस और घरेलू उत्पादों तक अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहा है. उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से उद्योगों को नई ऊर्जा मिली है, जिससे भारत अब गुणवत्ता और तकनीक के मामले में दुनिया का मुकाबला कर रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा, भारत अपने सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है. यह कदम न केवल हमारी वैज्ञानिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है. मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, केंद्र सरकार के सतत प्रयासों से उद्योगों को नई गति मिली है और दिल्ली सरकार निवेश, नवाचार और उद्योग-अनुकूल वातावरण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने उद्यमियों को दिल्ली में नई तकनीकों और स्टार्टअप्स के माध्यम से रबर क्षेत्र में मूल्य संवर्धन करने के लिए आमंत्रित किया.

## आबकारी नीति मामला- अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने उठाया ये कदम, 13 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी नीति मामला में अरविंद केजरीवाल के बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे. मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटाने की मांग की. दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार (13 अप्रैल) को मामले की सुनवाई करेगा. इससे पहले सोमवार (6 अप्रैल) को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे. इस दौरान उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को आबकारी नीति मामले में उन्हें और अन्य सभी आरोपियों को आरोप मुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से अलग किए जाने का आग्रह किया. हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के अलावा आप के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर और अरुण रामचंद पिल्लई सहित अन्य प्रतिवादियों ने भी जस्टिस शर्मा को सुनवाई से अलग किए जाने के आग्रह के साथ आवेदन दाखिल किए. अदालत ने केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों को सीबीआई की मुख्य याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 अप्रैल तक का समय अंतिम अवसर के तौर पर दिया है. सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे. उन्होंने दलील दी कि कोर्ट कोई नौटंकी का मंच नहीं है और अगर केजरीवाल मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने वकील को हटा देना चाहिए. यह पहली बार नहीं है, जब केजरीवाल ने अदालती कार्यवाही में खुद दलीलें पेश की हों. उन्होंने आगे कहा, इस देश में कुछ लोग हर किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाना अपना पेशा बना लेते हैं. इसे गंभीरता से लेना होगा. यह संस्था के खिलाफ आरोप है और हमें उस संस्था का समर्थन करना होगा. मेहता ने हाई कोर्ट को बताया कि आरोपमुक्त किए गए सात आरोपियों ने एक सुनियोजित योजना के तहत जस्टिस शर्मा को इस मामले की सुनवाई से अलग करने के अनुरोध को लेकर अदालत का रुख किया है.

# अटल बिहारी वाजपेयी- दुर्लभ चित्रों में जीवन यात्रा

भारतीय राजनीति के विस्तृत आकाश में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नक्षत्र थे, जिनकी चमक केवल सत्ता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जनमानस के हृदय में गहराई तक समाई हुई थी। उनकी राजनीति में विचार था, शब्दों में संवेदना थी और निर्णयों में राष्ट्रहित सर्वोपरि था। 312 पृष्ठ की मेरी नई कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेट्समैन इसी बहुआयामी व्यक्तित्व को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास है। अटल जी को केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। वे एक ऐसे इटरनल स्टेट्समैन थे जिनकी असली ताकत उनके भीतर के संतुलन, नैतिकता और आत्मचिंतन में निहित थी। वे राजनीति को केवल नीतियों और निर्णयों का खेल नहीं मानते थे, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण की एक सतत् साधना समझते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी—विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की गरिमा। संसद में जब वे बोलते थे तो शब्दों के साथ एक गहरी जिम्मेदारी भी झलकती थी। उनके भाषणों में आक्रोश नहीं, बल्कि तर्क और संवाद की शक्ति होती थी। वे विरोध को शत्रुता में नहीं बदलते थे, बल्कि उसे लोकतंत्र का आवश्यक अंग मानते थे। अटल जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि दृढ़ता और संवेदनशीलता साथ-साथ चल सकती हैं। एक ओर उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लिए, वहीं दूसरी ओर शांति और संवाद के द्वार हमेशा खुले रखे। यह संतुलन ही उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है। उनकी कविताओं में झलकता भाव उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखाई देता था। वे शब्दों के शिल्पी थे, चाहे वह कविता हो या कूटनीति। यही कारण है कि उनके निर्णयों में मानवीयता की झलक मिलती थी। वे केवल नीतियां नहीं बनाते थे, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की चिंता करते थे। इस पुस्तक के माध्यम से मेरा प्रयास रहा है कि पाठक अटल जी के उस पक्ष को समझ सकें जो अक्सर राजनीतिक विश्लेषण में छूट जाता है—उनका आंतरिक व्यक्तित्व, उनका आत्मसंवाद और उनका वह मानवीय पक्ष जिसने उन्हें «जननायक» बनाया। आज जब राजनीति में संवाद की कमी और विचारों की कठोरता बढ़ती दिखाई देती है, तब अटल जी का जीवन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और दिशा देने में होता है। अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित इस कॉफी टेबल बुक को तैयार करना अपने आप में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण, लेकिन भावनात्मक रूप से समृद्ध अनुभव रहा। सबसे बड़ी चुनौती थी—उनकी पुरानी तस्वीरों को संकलित करना और उन चित्रों में दिखाई दे रहे कार्यकर्ताओं, नेताओं और घटनाओं की सटीक पहचान करना। कई बार यह पता लगाना भी कठिन था कि कोई विशेष चित्र किस अवसर पर लिया गया था और उसमें उपस्थित व्यक्तियों का अटल जी से क्या संबंध था। इस पुस्तक को केवल चित्रों का संग्रह न बनाकर, उसे जीवंत और रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। हर तस्वीर के साथ न केवल उस घटना का विवरण दिया गया है, बल्कि उसमें मौजूद व्यक्तियों के साथ अटल जी के संबंधों और उनसे जुड़ी यादों को भी साझा किया गया है। यही इस पुस्तक की विशेषता है—यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि संबंधों और संवेदनाओं की कहानी भी कहती है। अटल जी के साथ मेरे लगभग 50 वर्षों के संबंधों की स्मृतियां जब भी मन में आती हैं, आंखें नम हो जाती हैं। मेरी शादी का एक चित्र इस पुस्तक में है, जिसमें अटल जी बारात में घोड़ी के साथ-साथ चलते दिखाई देते हैं। एक अन्य रोचक प्रसंग उस समय का है जब मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष बने थे—एक अनौपचारिक पार्टी में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेताजी, आइए हमारे आगे-आगे बैठिए, और वह क्षण एक सुंदर तस्वीर में कैद हो गया। प्रधानमंत्री निवास पर एक पारिवारिक मुलाकात के दौरान अटल जी ने जिस आत्मीयता से मेरे पूरे परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, वह अनुभव किसी दादाजी के स्नेह जैसा था—सहज, स्नेहपूर्ण और अपनापन भरा। यह पुस्तक 1924 से 2018 तक के अटल जी के जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उनकी शुरुआत, भारतीय जनसंघ की स्थापना, संसद में उनके प्रवेश, पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका, चुनावों में जीत-हार और यूनाइटेड नेशन में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण। प्रधानमंत्री के रूप में 1996 से 2004 तक का उनका कार्यकाल, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, लाहौर बस डिप्लोमेसी, आगरा समिट की असफलता और 2004 के चुनावों में हार,इन सभी क्षणों को भी चित्रों के माध्यम से सजीव किया गया है। साथ ही, भारत रत्न से सम्मानित होने तक की यात्रा भी इसमें समाहित है। इस पुस्तक में अटल जी के व्यक्तित्व के विविध रंग दिखाई देते हैं—कभी वे लिखते हुए, पढ़ते हुए, कविताएं रचते हुए नजर आते हैं तो कभी आंदोलनों में भाग लेते दिखते हैं, मार्च करते या जेल जाते हुए। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति मेरी 51 कविताएं के विमोचन के समय पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ उनकी प्रसन्न मुद्रा भी इसमें संजोई गई है। अटल जी के चेहरे पर सदैव एक अद्भुत शांति, सम्मोहन और मुस्कान रहती थी। उनकी ठहाकों से भरी हंसी और सहज व्यक्तित्व को देखकर इस पुस्तक का नाम मुस्कुराते अटल' भी रखा जा सकता था—एक ऐसा भाव जो आज के समय में दुर्लभ होता जा रहा है।

इस पुस्तक में लगभग हर उस प्रमुख नेता के साथ अटल जी के चित्र शामिल करने का प्रयास किया गया है जो उनके समय में सक्रिय थे, चाहे वे चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडीस, देवी लाल, जगजीवन राम, चंद्रशेखर या राम नारायण हों। नरेंद्र मोदी के साथ भी अटल जी के अनेक दुर्लभ चित्र इस पुस्तक में हैं। एक चित्र में वे होली के अवसर पर हाथ ऊंचाकर झूमते हुए दिखाई देते हैं।

विदेशी नेताओं, कलाकारों, खिलाड़ियों और अन्य क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों के साथ भी उनके चित्र इस पुस्तक में समाहित हैं। एक विशेष चित्र में वे अपने परिवार के साथ मस्ती में अत्यंत सहज और प्रसन्न दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के अभाव के समय में लिखे गए उनके व्यक्तिगत पत्र, जैसे मेरे पिता श्री जगदीश गोयल जी को लिखा गया उनका हस्तलिखित पत्र, इस पुस्तक को और भी मूल्यवान बनाते हैं। हमारे देश में राजनीतिक नेताओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक्स बहुत कम हैं, और जो हैं उनमें यह पुस्तक विशेष स्थान पा सकती है। इसे तैयार करने में चार वर्षों की अथक मेहनत लगी है। देश के विभिन्न हिस्सों से चित्र एकत्र किए गए, अनेक लोगों को पत्र लिखे गए, पत्र-पत्रिकाओं का सहारा लिया गया और आधुनिक समय में सोशल मीडिया से भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला। यह पुस्तक केवल अटल जी के जीवन का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक युग, एक विचारधारा और एक संवेदनशील व्यक्तित्व का जीवंत चित्रण है।

# प. बंगाल- मतदाताओं में बेचैनी

**पश्चिम** बंगाल में मतदान से पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है लेकिन लाखों मतदाता अनिश्चितता की स्थिति में हैं और चिंतित हैं। अत्यधिक लंबी सत्यापन प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित होने का खतरा है क्योंकि यह प्रक्रिया बहिष्कार का रूप ले चुकी है। मतदाता सूची से हटाए गए 6 लाख मतदाताओं के नाम विचाराधीन श्रेणी में डाले गए थे। इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि विचाराधीन प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मालदा में प्रदर्शनकारी मतदाताओं द्वारा एसआईआर अधिकारियों का घेराव और उन्हें कई घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना के पीछे राजनीतिक सुनियोजित घटनाक्रम के तार राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो (एनआईए) ढूंढ रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए पश्चिम बंगाल प्रशासन को खूब खरी-खोटी सुनाई थी लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया अब बहिष्कार में तब्दील हो गई है। क्योंकि लोग लंबी प्रक्रिया में घंटों इंतजार करने की बजाय घर में ही बैठक पसंद कर रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अर्जी सुनने के लिए गठित न्यायाधिकरणों ने अभी काम भी शुरू नहीं किया है और एसआईआर में हुई गड़बड़ियों के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख को वोट डालने का मौका मिल गया है। मोहताब शेख का नाम 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के विचाराधीन मामले के कालम में डाल दिया गया था। एक न्यायाधिकरण ने उनका नाम बहाल कर दिया। मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाने के कारण मोहताब शेख नामांकन भी दाखिल नहीं कर सके थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम ने शेख के मामले की सुनवाई के लिए साल्ट लेक में एक विशेष सुनवाई आयोजित की। इस दौरान शेख ने अपना पासपोर्ट प्रस्तुत किया। यह वही दस्तावेज था जो उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया था। न्यायमूर्ति शिवज्ञानम ने सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच की और अपने आदेश में कहा कि निर्वाचन आयोग ने न्यायिक अधिकारी द्वारा निर्णय के दौरान उनका नाम हटाए जाने से संबंधित परिस्थितियों को प्रस्तुत न करने के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया था।

न्यायमूर्ति शिवज्ञानम ने अंततः यह माना कि शेख द्वारा दिया गया पासपोर्ट पर्याप्त था और चुनाव आयोग को रविवार रात 8 बजे तक एक अतिरिक्त सूची के माध्यम से उन्हें मुर्शिदाबाद का वैध मतदाता घोषित करने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग ने 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी जिसमें लाखों मतदाताओं को विचाराधीन के रूप में चिह्नित किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं और गड़बड़ियों का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 326 में निहित संवैधानिक वादा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता बनने का अधिकार होगा, पूरा नहीं होगा। क्या गड़बड़ियों वाली मतदाता सूची से निष्पक्ष और ईमानदार चुनावों की उम्मीद की जा सकती है? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार प्रभावित हो रही है और जनता के बीच इसका भरोसा काफी कम हो चुका है। चुनाव आयोग, जिसका प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने और मतदाता समावेशन को प्राथमिकता देने का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे इन गंभीर चिंताओं का समाधान अवश्य करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय, जिसने पिछले वर्ष बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के दौरान हस्तक्षेप करके प्रक्रिया को मतदाताओं की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में मदद की थी, उसे पश्चिम बंगाल पर भी नजर रखनी चाहिए। शुरुआत से ही, बंगाल में किया गया विशेष गहन संशोधन अन्य राज्यों की तुलना में अधिक जटिल प्रतीत होता है। समय की कमी के बीच कई विवादास्पद नए प्रावधान लागू किए गए। फरवरी में न्यायालय ने एसआईआर को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करते हुए लगभग 500 न्यायिक अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए थे। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है और प्रक्रिया अधूरी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया काफी विवादित रही है। 28 फरवरी को जारी की गई राज्य की अंतिम वोटर लिस्ट में 6.44 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे। इस प्रक्रिया के तहत करीब 63 लाख 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट' मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। वहीं करीब 60 लाख मतदाताओं की स्थिति 'जांच के अधीन' बनी रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद करीब 700 न्यायिक अधिकारियों को 'जांच के अधीन' मौजूद वोटरों के रिकॉर्ड की जांच करने और उनकी मतदान पात्रता तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब तक 52 लाख से ज्यादा 'जांच के अधीन' रखे गए मामलों का निपटारा किया जा चुका है, लेकिन इस प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं की सही संख्या अभी भी पता नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या लाखों मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। कोलकाता स्थित थिंकटैंक 'सबर इंस्टीट्यूट' के एक विश्लेषण के अनुसार, पहले और दूसरे चरण में न्यायिक अधिकारियों ने जिन वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया है उनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं का है। एसआईआर प्रक्रिया के कारण मतदाताओं में बेबसी की भावना पैदा हुई। उनकी उदासीनता मतदाता के तौर पर अधिकार को लेकर चिंताओं का ही एक रूप है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल के मतदाताओं की चिंता दूर कैसे की जाए।

सम्पादकीय...

# मरघट के चौकीदारों की नकेल कसिए !

**अमेरिका**-इजराइल और ईरान की जंग शुरू होने के बाद जैसे ही एलपीजी गैस की कमी की आशंका पैदा हुई थी, तब मैंने लिखा था कि ढाबों को गैस सिलेंडर मिलता रहे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खासकर ट्रक ड्राइवरों के लिए तो भोजन का एकमात्र माध्यम ये ढाबे ही होते हैं। आशंका सच साबित हुई है। बहुत से ढाबे तो बंद हो चुके हैं। जो खुले हैं, वे लकड़ियां जला रहे हैं और एक बार जो खाना बना लिया, वही दिन भर परोस रहे हैं। कई जगह तो खाना मिल भी नहीं रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी कई होटल और रेस्तरां इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। कामकाजी महिलाएं परेशान हैं कि काम पर जाएं या सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहें। सरकार कहती है कि सिलेंडर की कोई कमी बिल्कुल नहीं है, मगर सप्लाई चेन में जरूर दिक्कतें आ रही हैं। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात होर्मुज जलडमरूमध्य से करता है। एलपीजी लदे जहाज पहले 11 दिनों में होर्मुज से भारत पहुंच जाया करते थे। इस रास्ते से ईरान की मददशीलता के कारण जहाज अभी भी आ रहे हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम है और समय ज्यादा लग रहा है। दूसरे देशों से भी एलपीजी लदे जहाज आ रहे हैं, लेकिन वो रास्ते बहुत लंबे हैं। देश में एलपीजी मिलने की समस्या के कारण सरकार ने यह तय किया कि पहले घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता में नहीं है। नतीजतन शहरी क्षेत्र के कई होटलों और रेस्तरां में घरेलू गैस का उपयोग होने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यावसायिक एलपीजी के साथ घरेलू एलपीजी की भी धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इस कालाबाजारी की चर्चा से पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कर लीजिए। भारत में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या करीब 33 करोड़ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन 55 लाख घरेलू गैस सिलेंडर की मांग रहती है। अब यह बढ़कर 75 लाख सिलेंडर प्रतिदिन हो गई है, सवाल लाजमी है कि 20 लाख सिलेंडर प्रतिदिन कहां जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतने सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है तो फिर कालाबाजारी क्यों? क्या ये केवल पैनिक बुकिंग का नतीजा है? या फिर मरघट के चौकीदार सक्रिय हो गए हैं जो संकट के वक्त भी केवल अपने मुनाफे की बात ही सोचते हैं! आज आप बुकिंग कराएं तो सिलेंडर भले ही न मिले लेकिन कालाबाजार में दोगुनी कीमत पर आपको बड़ी सहजता से सिलेंडर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि कालाबाजारी का ये पैसा आम आदमी की जेब से लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भारत में पेट्रोलियम कंपनियां सौ फीसदी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और एलपीजी की कमी को लेकर लोग आशंकित न हों लेकिन हालात ये हैं कि लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर स्टूल इंडक्शन और इन्फ्रारेड इंडक्शन चूल्हे खरीदने शुरू किए, तो उनकी कीमतें आसमान छूने लगीं, यहां भी मरघट के चौकीदारों ने अपना खेल दिखा दिया, जो इंडक्शन दो हजार रुपए का मिल रहा था, वह अभी चार से पांच हजार रुपए का मिल रहा है।

# बंगाल में लाखों लोग वोट नहीं डाल पाएंगे!

**भारत में राज्यपाल बनने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटना कोई अनोखी बात नहीं है। कई नेता राज्यपाल रहने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटे और मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बने हैं। सुशील कुमार शिंदे से लेकर मोतीलाल वोरा तक की मिसालें हैं। भाजपा ने भी उत्तर प्रदेश में बेबीरानी मौर्य से लेकर तमिलनाडु में तमिलिसाई सौंदर्यराजन तक को चुनाव लड़वाया। लेकिन अगर भाजपा का कोई नेता बुजुर्ग हो और राज्यपाल रहा हो फिर भी उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले तो यह भाजपा के कई बुजुर्ग नेताओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। असल में भाजपा ने एक अघोषित नियम बना रखा है कि 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अपवाद बनाया गया है। लेकिन इस बार भाजपा केरल में पूर्व राज्यपाल के.राजशेखरन को चुनाव लड़ा रही है, जिनकी उम्र 73 साल है। गौरतलब है कि कुम्मनम राजशेखरन मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। वे इस बार अरानमुला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक समय दक्षिण भारत और खास कर केरल की राजनीति में वे भाजपा का चेहरा माने जाते थे। लंबे समय तक संघ प्रचारक और भाजपा के नेता रहे राजशेखरन की कुल संपत्ति एक लाख रुपए की है।**

ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार लाखों लोग विधानसभा चुनाव में वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसका कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में हुई देरी है। असल में किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम ज्यादा जटिल हो गया।

चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों के मुकाबले तार्किक विसंगति का मुद्दा बंगाल में ज्यादा उठाया और लाखों मतदाताओं के दस्तावेज की कई-कई बार जांच हुई। एक बार और अभी ट्रिब्यूनल में जांच होनी है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार लाखों लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि यह सवाल अपनी जगह है कि क्या लाखों लोगों को वोट डालने से वंचित करके चुनाव कराया जा सकता है? इस मामले में हर जगह सुप्रीम कोर्ट शामिल है और सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाजा है कि लोगों के नाम कटेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके बावजूद चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। इसका एक संकेत सुप्रीम कोर्ट की पिछले बुधवार की टिप्पणी से भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की वजह से एक चुनाव में किसी मतदाता का नाम कट जाने का यह मतलब नहीं है कि उसका नाम हमेशा के लिए कट गया। जाहिर है कि नाम कटने के बाद भी चुनाव की प्रक्रिया तय शिड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ेगी। इससे सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग जान-बूझ कर किसी खास मकसद से लाखों लोगों को वोट डालने से वंचित रखेगा?

### पुडुचेरी में अगर हारी तो कांग्रेस खुद जिम्मेदार

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए सबसे आदर्श स्थिति दक्षिणी राज्यों में है। चुनाव सर्वेक्षणों में बताया जा रहा है कि कांग्रेस केरल में चुनाव जीत सकती है। तमिलनाडु में भी डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन वापस सत्ता हासिल कर सकता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मामला उलझा हुआ है। 30 विधानसभा सीटों वाले राज्य पुडुचेरी में 2016 में कांग्रेस जीती थी और अहमद पटेल के करीबी रहे वी नारायणसामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन 2021 के चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी और कांग्रेस के कारण डीएमके भी हारी। इस बार भी अगर पुडुचेरी में एनडीए चुनाव जीतता है तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी होगी। पुडुचेरी में कांग्रेस के लिए माहौल ठीक नहीं है। इसके बावजूद जैसे पिछली बार कांग्रेस ने जिद करके ज्यादा सीटें लीं और गठबंधन को हरवाया उसी तरह इस बार भी वह ज्यादा सीटें लेकर लड़ रही है। गौरतलब है कि 2021 में कांग्रेस 14 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ दो सीट जीत पाई। दूसरी ओर डीएमके 13 सीटों पर लड़ कर छह पर जीती। इससे पहले 2016 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थीं। नारायणसामी ने कांग्रेस को 17 से दो सीट पर ला दिया। इस बार भी कांग्रेस ने जिद करके 16 सीटें ली हैं और डीएमके को पहले की तरह 13 सीटें दी हैं। यही नहीं, बाद में कांग्रेस ने पांच और सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए। इसीलिए अगर इस बार भी गठबंधन हारता है तो जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी।

### सीसीटीवी लगाओ, उतारो और फिर लगाओ

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुरक्षा और खास कर महिला सुरक्षा का हवाला देकर लाखों सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। अब रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार कह रही है कि ये चाइनीज कंपनी के सीसीटीवी कैमरे हैं, इसलिए उनको हटाया जाएगा। यह काम शुरू भी हो गया है। एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे उतारे जा रहे हैं। इन कैमरों को लगाने का काम 2020 में शुरू हुआ था और 2022 के अंत तक यह काम चला था। अब इतनी जल्दी इनको हटाया जा रहा है। इनकी जगह नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वैसे पूरी दिल्ली में कुल दो लाख 74 हजार से कुछ ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो बहुत कम हैं। बहरहाल, भाजपा सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली में लगे एक लाख 40 हजार कैमरे एक ही चाइनीज कंपनी हिकविजन के हैं। इससे जासूसी का खतरा बताया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि अगर चीन की कंपनी के कैमरे होने की वजह से जासूसी का खतरा है तब तो पूरे देश में इस किस्म का खतरा होगा। भारत में कई संवेदनशील जगहों पर चीन की कंपनियों के कैमरे लगे हैं। सिर्फ कैमरे ही नहीं, बल्कि दूसरे इलेक्ट्रानिक उपकरण भी चीनी कंपनियों के हैं। भारत में तो ज्यादातर लोगों के हाथ में चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन हैं, जिनसे करोड़ों क्या अरबों तस्वीरें रोज खींची जाती हैं और वीडियो बनाए जाते हैं। अगर चीनी उपकरणों से जासूसी होने का खतरा है तब तो सारे उपकरण बदलने चाहिए। दिल्ली के एक लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरे बदल देने से क्या चीन की जासूसी से छुटकारा मिल जाएगा?

### ममता का फिर दिल्ली चलो' का ऐलान

ममता बनर्जी ने एक बार फिर दिल्ली चलो' का ऐलान कर दिया है। वे हर विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का ऐलान करती हैं। उनकी पार्टी भी इस तरह की घोषणा करती है। पिछले चुनाव में यानी 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने बहुत साफ तरीके से कहा था कि दिल्ली का रास्ता बंगाल से होकर जाएगा। यह भी कहा गया था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति के लिए कूच करेंगी और 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष के एक मजबूत गठबंधन इंडिया' ब्लॉक का गठन हुआ तो ममता बनर्जी ने खुद को उससे अलग कर लिया और बंगाल की राजनीति ही करती रहीं। अब फिर उनके दिल्ली फतह करने की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार उन्होंने खुद ही कहा है कि 2026 में बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जीतेंगी। माना जा रहा है कि हर बार बांग्ला मानुष को यह संदेश दिया जाता है कि उनकी नेता ममता बनर्जी देश की नेता बनने लायक हैं और वे जीतीं तो देश की राजनीति करके प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। गौरतलब है कि आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भागीदारी बंगाल की रही थी लेकिन आज तक वहां का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सका है। यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस बात का ज्यादा प्रचार कराते हैं कि ममता दिल्ली जाएंगी। वे दिल्ली जाएंगी तभी कोलकाता में मुख्यमंत्री की कुर्सी अभिषेक के लिए खाली होगी।

### बुजुर्ग राज्यपालों के लिए राहत की बात

भारत में राज्यपाल बनने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटना कोई अनोखी बात नहीं है। कई नेता राज्यपाल रहने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटे और मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बने हैं। सुशील कुमार शिंदे से लेकर मोतीलाल वोरा तक की मिसालें हैं। भाजपा ने भी उत्तर प्रदेश में बेबीरानी मौर्य से लेकर तमिलनाडु में तमिलिसाई सौंदर्यराजन तक को चुनाव लड़वाया। लेकिन अगर भाजपा का कोई नेता बुजुर्ग हो और राज्यपाल रहा हो फिर भी उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले तो यह भाजपा के कई बुजुर्ग नेताओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। असल में भाजपा ने एक अघोषित नियम बना रखा है कि 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अपवाद बनाया गया है। लेकिन इस बार भाजपा केरल में पूर्व राज्यपाल के.राजशेखरन को चुनाव लड़ा रही है, जिनकी उम्र 73 साल है। गौरतलब है कि कुम्मनम राजशेखरन मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। वे इस बार अरानमुला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक समय दक्षिण भारत और खास कर केरल की राजनीति में वे भाजपा का चेहरा माने जाते थे। लंबे समय तक संघ प्रचारक और भाजपा के नेता रहे राजशेखरन की कुल संपत्ति एक लाख रुपए की है। बहरहाल, वे राज्यपाल रहे हैं, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए भाजपा के जो नेता राज्यपाल बनाए गए हैं और जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता होने पर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है।

# बागी सिपाहियों को सबक सिखाने के मूड में कांग्रेस

**पांच** राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का दांव चूंकि दो राज्यों में ही सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका सारा ध्यान इन्हीं दो राज्यों पर है। असम और केरल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति अलग-अलग है। इसलिए दोनों ही राज्यों में उसकी चुनौतियां अलग हैं, इसलिए उसकी लड़ाई के रूप और तरीके अलग-अलग हैं। हरियाली और समुद्री किनारे के चलते केरल को खूबसूरत राज्यों में शुमार किया जाता है। इस खूबसूरती की ही वजह से केरल को 'भगवान का देश' कहा जाता है। बारह साल से केंद्रीय सत्ता से दूर कांग्रेस को उम्मीद भगवान के इसी देश से ही ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरह इस राज्य से उसे समर्थन मिला था, उसकी वजह से उसकी उम्मीदों का परवान चढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन यहां उसकी चुनौती भगवान को न मानने वाली विचारधारा से है। केरल की सत्ता पर काबिज जिस वाममोर्चा से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का मुकाबला है, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ बने विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस उसी वाममोर्चे के साथ है। स्थानीय स्तर पर विरोध और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का विरोधाभास अगर सर्वाधिक शिक्षित राज्य में भारी पड़ सकता है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में राजधानी तिरुअनंतपुरम् में जीत हासिल कर चुकी बीजेपी इस विरोधाभास को खूब उछाल रही है। वैसे तो बीजेपी का दावा है कि इस बार भगवान के देश में भगवा ध्वज फहरने जा रहा है, हालांकि अब तक चुनावी अभियान से साफ है कि बीजेपी को वैसी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन बीजेपी का मौजूदा जोर आखिरी दम तक हार नहीं मानने का है। इसलिए पार्टी की कोशिश सीपीएम की अगुआई वाले वाममोर्चे और कांग्रेस की अगुआई वाले संयुक्त मोर्चे के विरोधाभास को उजागर करने पर है। पार्टी को लगता है कि देश के इस सर्वाधिक साक्षर राज्य में अगर जनता ने इस विरोधाभास को समझ लिया तो राज्य के चुनावी नतीजे 2017 के उत्तर प्रदेश के परिणामों की तरह आश्चर्यजनक रूप से अपने पक्ष में किए जा सकते हैं। 2017 में किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। इसी कोशिश के तहत अमित शाह केरल की करीब 19 प्रतिशत जनसंख्या वाले ईसाई समुदाय से लगातार संपर्क कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, केरल के कुल 3.34 करोड़ निवासियों में से लगभग 61.41 लाख ईसाई हैं, जो मुख्य रूप से मध्य केरल में केंद्रित हैं। पारंपरिक रूप से केरल में यह समुदाय कांग्रेस का सहयोग करता रहा है, लेकिन बीजेपी की कोशिश इस समुदाय को कांग्रेस से तोड़ने की रही है। हालिया अतीत के कुछ चुनावों में यह समुदाय बीजेपी के साथ खड़ा होता नजर आया है। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित लव जेहाद का शिकार केरल में यह समुदाय भी होता रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर इस समुदाय में भी कुछ वैसा ही गुस्सा है, जैसा उत्तर भारत में हिंदू समाज में ऐसा नजर आता है। कांग्रेस का संकट है कि वह वाममोर्चा का विरोध और समर्थन की उलटबांसी को सटीक काट नहीं खोज पा रही है। इस वजह से राज्य का चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। वैसे बीजेपी जिस तरह की कोशिश करती नजर आ रही है, उससे सबसे ज्यादा संकट में कांग्रेस की संभावनाएं ही नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की रणनीति कांग्रेस को इस राज्य की सत्ता से दूर रखने की ही है। पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य असम की जहां तक बात है, तो वहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। कांग्रेस की चिढ़ यह है कि बीजेपी जिस हिमंत बिस्वसरमा के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, वह कभी कांग्रेस का ही चेहरा होते थे। कांग्रेस अपने इस पूर्व नेता को इस बार हर हाल में सबक सिखाने के मूड में नजर आ रही है। जिस तरह उनकी पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन-तीन पासपोर्ट हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का आरोप है कि रिंकी भुइयां सरमा के पास संयुक्त अरब अमीरात, एंटीगुआ और बारबुडा एवं मिस्र का पासपोर्ट है। कांग्रेस ने इसके समर्थन के कुछ दस्तावेजों की कॉपी भी दिखाई है। हालांकि हिमंत बिस्वसरमा का कहना है कि कांग्रेस हताशा में है और उनकी ओर से कांग्रेस के नेताओं पर मानहानि का केस दायर करने की भी बात कही जा रही है। कांग्रेस एक तरह से अपने इस पुराने सिपाही को भ्रष्टतम साबित करने की कोशिश में है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि हिमंत के पास अमेरिका में भी कंपनी है, जिसमें बावन हजार करोड़ रुपए जमा है। कांग्रेस का यह आरोप राहुल गांधी के आरोपों का विस्तार ही लगता है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले उन्हें अपने पुराने सहयोगी को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। राहुल गांधी उन्हें सत्ता में वापसी के बाद जेल भेजने की बात कहते रहे हैं। कांग्रेस की इन आरोपों के जरिए कोशिश सिर्फ हिमंत को ही सवालों के घेरे में रखना नहीं है, बल्कि बीजेपी को भी भ्रष्टाचार बताने की भी है। वैसे हिमंत भी राहुल गांधी की आलोचना करते रहे हैं। अपने कांग्रेस छोड़ने की वजह वे राहुल गांधी को ही बताते रहे हैं। दोनों के रिश्तों के संदर्भ में मौजूदा आरोपों को देखें तो यह निजी खुन्नस का भी मामला लगता है। हिमंत इन आरोपों को निजी खुन्नस बताने और असम के लोगों को समझाने की कोशिश में लगे हैं। अगर वे इसमें कामयाब रहे तो असम में कांग्रेस की चुनावी संभावना दूर होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए उत्तर पूर्व में अपनी मौजूदगी बनाए रखना दूर की कौड़ी हो जाएगा। इसका कारण यह है कि हिमंत पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी का चेहरा और संकट मोचक बन चुके हैं। अगर कांग्रेस की कोशिशें कामयाब रहीं तो पूर्वोत्तर में बीजेपी की राह कठिन हो जाएगी। हिमंत की हार उसकी चुनावी संभावनाओं पर बड़ा प्रश्नचिन्ह बनकर उभरेगी। असम पर काबू पाने के लिए कांग्रेस ने अपने हरावल दस्ते के हर हथियार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस की कोशिशों को पलीता उसकी प्रेस कांफ्रेंस में ही लगता दिखा, जब राष्ट्रीय मीडिया के एक पत्रकार ने उस कंपनी की वेबसाइट खोलकर उसकी स्थापना के तथ्य कांग्रेस प्रवक्ता के सामने पेश करने शुरू कर दिए, जो कांग्रेस के दावे के ठीक उलट नजर आ रहे थे। इसका माकूल और संतोषजनक जवाब कांग्रेस प्रवक्ता नहीं दे पाए। असम से सटे पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहां तो वह लड़ती भी नहीं दिख रही। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस की सिपाही रहीं। केरल की तरह पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस विरोधाभास से जूझ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर वह ममता के साथ है, लेकिन राज्य में उसकी पूरी कोशिश ममता को हिमंत की तरह सबक सिखाने की ही लग रही है। दरअसल राज्य में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। हालांकि 2023 में मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले की सागरदीघी सीट के उपचुनाव में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को हराकर विधानसभा में अपना खाता खोलने में सफल रही थी। मुस्लिम बहुल विधानसभा में कांग्रेस की जीत से ममता की नींद उड़ गई थी। राज्य के करीब पैंतीस फीसद मुस्लिम वोट बैंक में सेंध का डर उन्हें सताने लगा। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन सागरदीघी शुरू किया और वहां से जीते कांग्रेसी विधायक बायरन विश्वास को तृणमूल कांग्रेस में शामिल करा दिया। कांग्रेस ने इसे विश्वासघात माना और लगता ऐसा है कि वह ममता को इन चुनावों में सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की ग्यारह मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर उसके प्रत्याशी पहले नंबर पर रहे थे। इसलिए कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि विधानसभा चुनावों में उसे मुस्लिम वोटरों का साथ मिल सकता है। उसकी पूरी रणनीति इसी लिहाज से आगे बढ़ रही है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बन्ना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैन्सलोला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/[illegible])

# ताबड़तोड़ घटनाओं से दहला कसानगंज, दिनदहाड़े लूट और रात में फायरिंग से फैली दहशत

कसानगंज, कुशीनगर।

नगर कसानगंज में सोमवार को एक ही दिन हुई तीन बड़ी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। नगर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन घटनाओं से भय और दहशत का माहौल है। सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे सुभाष चौक स्थित गांधी गली में दिनदहाड़े एक महिला से झपट्टा मारकर एक लाख रुपये लूट लिए गए। खैरटवा निवासी संगीता गुप्ता, पत्नी रघुपति गुप्ता, पास के स्टेट बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रही थीं, तभी बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। यह क्षेत्र घनी आबादी और भीड़भाड़ वाला है, ऐसे में घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। इस घटना के करीब छह घंटे बाद रात लगभग 11 बजे वार्ड संख्या तीन स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल की गली में बाइक सवार तीन बदमाशों ने वार्ड सदस्य मोहम्मद आरिफ के घर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। दरवाजा नहीं खुलने पर बदमाशों ने अवैध असलहे से तीन राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी और मौके से फरार हो गए। इसके तुरंत बाद करीब 11:10 बजे सच्चिदानंद कॉलेज रोड पर समाजसेवी विक्की मद्धेशिया के घर के पास भी बदमाशों ने पहुंचकर गाली-गलौज और धमकी देते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। लगातार हुई इन घटनाओं से पूरा इलाका थर्रा गया। हालांकि, संयोगवश दोनों ही मामलों में किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पीड़ितों और स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। मोहम्मद आरिफ ने उसी रात और विक्की मद्धेशिया ने मंगलवार दोपहर पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने और जांच की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी क्षेत्र में दुर्गौली माता मंदिर से जेवर चोरी, मंगल बाजार में फायरिंग, बभनौली और चांदनी चौक जनता मार्केट में वारदात जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

# संगठन सृजन अभियान के तहत बाबरपुर जिला बैठक संपन्न

दिल्ली।( इंद्रजीत सिंह ) संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत बाबरपुर जिले की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर एआईसीसी ऑब्जर्वर एवं पूर्व सांसद आर.सी. खूंटिया, जिला अध्यक्ष राज कुमार जैन, लक्ष्मण रावत, पूर्व विधायक राजेश लिलोठिया, विपिन शर्मा, भीष्म शर्मा, अब्दुल रहमान, हाजी इशराक, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश जैन, सुखबीर सिंह, निगम पार्षद हाजी जरीफ, पूर्व पार्षद चौधरी अजीत सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेशवती चौहान सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने सुझाव साझा किए और संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंगत राम सिंघल ने कहा, कांग्रेस का संगठन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हम हर कार्यकर्ता को जोड़ते हुए बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। जब संगठन मजबूत होगा, तभी हम जनता की आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठा पाएंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ सकेंगे। वक्ताओं ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका में लाना है, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस और अधिक मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को उठा सके।बैठक का समापन संगठन को मजबूत बनाने और आपसी समन्वय बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ।

# हनुमान जयंती पर जाखू मंदिर में गूंजा जयकारा, अजय माकन ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली।(आकाश शक्य) जयंती के पावन पर्व पर शिमला स्थित विश्वविख्यात श्री हनुमान मंदिर, जाखू में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के कोषाध्यक्ष श्री अजय माकन ने भगवान हनुमान के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर जय श्री राम और बजरंगबली की जय के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच श्री माकन ने देशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हनुमान जी की अटूट भक्ति, अद्भुत शक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव हम सभी के जीवन के

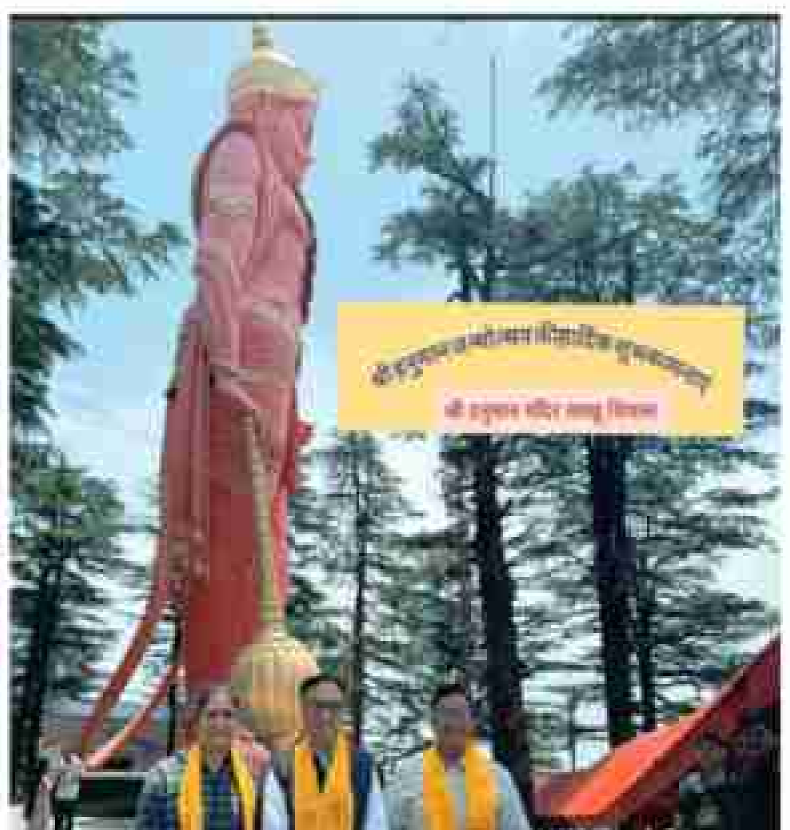

लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने भगवान से देश में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना की तथा कहा कि आज के समय में हनुमान जी के आदर्शों–समर्पण, साहस और सेवा–को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर उनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु भी उपस्थित रहे, जिन्होंने भक्ति भाव से पूजा में भाग लिया।

# भूमि की फर्जी दस्तावेज पर वसीयत कराकर बेचने का प्रयास

## पीड़ित बुज़ुर्ग एसडीएम से शिकायत कर न्याय की लगाई गुहार

महराजगंज।

निचलौल क्षेत्र के गांव छितौना निवासी एक व्यक्ति की भूमि को एक शख्स ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर वसीयत करा ली। उसके बाद शख्स उक्त भूमि को बेचने के प्रयास में जुट गया है। मामले की जानकारी होने पर भूमि के मालिक पीड़ित व्यक्ति मंगलवार को तहसील पहुंच एसडीएम के सामने फफक पड़ा। उसके बाद पीड़ित एसडीएम के पूछताछ में पूरी बात बताने के साथ ही शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। छितौना निवासी राजेंद ने बताया है कि वह दलित समुदाय के रामहरख और बलासी से आराजी संख्या 381 रकवा 0.291 हेक्टेयर भूमि बैनामा लिए है। पीड़ित का आरोप है कि पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से उक्त भूमि का वसीयत करा ली है। हालांकि उक्त व्यक्ति सामान्य समुदाय से आता है। इतना ही उक्त विवादित भूमि का मुकदमा उपजिलाधिकारी न्यायिक, उपजिलाधिकारी के साथ ही सिविल जज (अवर खंड) महराजगंज और अनुसूचित न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद भी शख्स उक्त विवादित भूमि को बेचने के फिराक है। ऐसे में मामले की जांच कर भूमि को बेचने से रोकने के साथ ही शख्स पर कानूनी कार्रवाई की जाय। वही एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है। उक्त भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

# गैस नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं ने तहसील पहुंच किया हंगामा

निचलौल।

क्षेत्र स्थित एक गैस एजेंसी पर गैस नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ता मंगलवार को आक्रोशित हो उठे। उसके बाद आक्रोशित उपभोक्ता गोलबंद होकर गैस एजेंसी से तहसील परिसर जा पहुंचे। जहां पर उपभोक्ता गैस एजेंसी के कर्मियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हंगामा करने लगे। इसी बीच उपभोक्ताओं की हंगामा की आवाज सुन मौके पर तहसीलदार आ पहुंचे। तहसीलदार के काफी प्रयास करने और आश्वासन के बाद उपभोक्ता किसी तरह शांत हुए। उसके बाद तहसील के कर्मियों ने किसी तरह राहत की सांस ली। तहसील पर हंगामा कर रहे उपभोक्ता

**तहसीलदार के आश्वासन पर शांत हुए आक्रोशित उपभोक्ता**

अनिल, गुड्डु, राजेश, सुनीता आदि ने बताया कि वह लोग करीब एक महीने से गैस के लिए एजेंसी का चक्कर लगा रहे है। लेकिन एजेंसी के कर्मियों की मनमानी के चलते उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा है। हद तो तब हो गई जब वह लोग गैस के लिए बुकिंग करने के बाद रकम भी जमा कर दिए। उसके बाद भी गैस एजेंसी से उन लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बुकिंग गैस मोबाइल पर मैसेज के जरिए कई दिन पहले ही डिलेवरी दिखाया जा रहा है। वही गैस के एक कर्मी ने बातचीत में बताया कि एजेंसी कर हर रोज गैस आ रही है। जिसे नियम के मुताबिक उपभोक्ताओं में वितरण भी किया जा रहा है। एजेंसी पर उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक होने के चलते थोड़ी दिक्कत हो रही है। जिसे लगातार सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। वही तहसीलदार अमित कुमार सिंह ने बताया कि आक्रोशित उपभोक्ताओं से उनकी समस्याओं को सुनने के बाद जल्द निस्तारण के लिए गैस एजेंसी के कर्मियों से वार्ता की गई। उसके बाद तहसील कर पहुंचे सभी उपभोक्ताओं को गैस वितरण के लिए सूची तैयार कर गैस देने के लिए निर्देशित किया गया है।

# 166 करोड़ की लागत से बदलेगी देवरिया बस स्टेशन की सूरत, पीपीपी मॉडल पर बनेगा प्रदेश का चौथा सबसे भव्य टर्मिनल

**जर्जर भवन और जलभराव से मिलेगी मुक्ति - तीन लाख वर्गफुट में सिनेमाघर, मॉल और होटल जैसी सुविधाओं से लैस होगा नया परिसर**

**कैबिनेट की मुहर - प्रशासनिक अड़चनों को पार कर धरातल पर उतरेगी योजना, जल्द शुरू होगी टेंडर की**

**विधायक शलभ मणि की पैरवी लाई रंग, कैबिनेट ने दी मंजूरी**

देवरिया। जनपद के लाखों यात्रियों के लिए वह इंतज़ार खत्म होने वाला है, जो वर्षों से एक अदद आधुनिक बस स्टेशन की बाट जोह रहे थे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में देवरिया में 166 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक और भव्य बस स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है।पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित यह प्रोजेक्ट न केवल जनपद की परिवहन व्यवस्था को सुधारेगा, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को भी एक नई पहचान देगा। खास बात यह है कि आवंटित बजट और भव्यता के मामले में यह प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा बस स्टेशन होगा, जो लखनऊ, देवीपाटन और सोनौली जैसे बड़े टर्मिनल्स को टक्कर देगा। जिसकी लागत 166 करोड़ रुपये आंकी गई है। वर्तमान में देवरिया का बस स्टेशन अपनी बदहाली के लिए सुर्खियों में रहता है। टूटी सड़कें, बरसात में जलभराव और बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के पीछे देवरिया सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की लंबी और कठिन राजनीतिक लड़ाई रही है। विधायक बनने के बाद से ही शलभ मणि त्रिपाठी इस बस स्टेशन की बदहाली को लेकर मुखर रहे। उन्होंने न केवल हर विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, बल्कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत भेंट कर जनपद की इस जरूरत को विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा।

कई बार प्रशासनिक और विभागीय अड़चनें आईं, जमीन को लेकर भी पेंच फंसा, लेकिन विधायक की जिद थी कि देवरिया को एक ऐसा बस स्टेशन मिले जो जिले की नई पहचान बने। पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर बनने वाला यह बस स्टेशन करीब तीन लाख वर्गफुट के विशाल क्षेत्र में फैला होगा। इसे केवल एक बस अड्डे के तौर पर नहीं, बल्कि एक आधुनिक कमर्शियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ यात्रियों को बस पकड़ने के साथ-साथ शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, होटल और बेहतरीन रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। पहले इस स्टेशन को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन विधायक और प्रशासन के आपसी समन्वय के बाद अब यह शहर के भीतर ही अपनी पुरानी जगह पर भव्य रूप लेगा। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद अब विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

# वार्षिकोत्सव में झलकी प्रतिभा और संस्कार, छात्र-अभिभावकों का हुआ सम्मान

रामकोला, कुशीनगर।

कंपोजिट विद्यालय पकड़ी बांगर, रामकोला में वार्षिकोत्सव एवं छात्र-अभिभावक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कार और प्रतिभा का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिला। बच्चों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनों को भाव-विभोर कर दिया। समारोह के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रामकोला डॉ. प्रभात चंद्र राय ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार और प्रतिभा का विकास ही वास्तविक प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि छात्र एवं अभिभावकों का सम्मान उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, जो सराहनीय पहल है।

विशिष्ट अतिथि शिक्षक आर. के. भट्ट ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला है, जहां बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या ने कहा कि यह अवसर केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि वर्षभर की उपलब्धियों, प्रतिभाओं और परिश्रम का उत्सव है। कार्यक्रम के अंत में सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानवर्धन गोविंदराव ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्रीकांत यादव, मंत्री अमित श्रीवास्तव, पूर्व एआरपी योगेंद्र शुक्ला, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉ. शंकर दयाल पाठक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा एआरपी अजय विश्वकर्मा, विकास तिवारी, प्रणव चतुर्वेदी, सुरेंद्र प्रसाद, बबन प्रसाद, जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमचंद गौतम, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संगठन मंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष केशव गोविंद राव, कार्यक्रम के नोडल शिक्षक चंद्रशेखर चांद, शैलेश कुमार सिंह, अनवर अंसारी, लालमन यादव, अखिलेश यादव, सत्यवती पांडे और सुशीला शर्मा सहित विद्यालय परिवार व बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।

# सबरीमाला पर अदालत के सात सवाल; जस्टिस नागरत्ना बोलीं- महिलाएं केवल तीन दिन अछूत नहीं हो सकती

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को केरल के सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धर्मों में और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत ने नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ का औपचारिक गठन किया है, जो 2018 के फैसले के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिकाओं पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने सबरीमाला संदर्भ के दौरान कहा कि किसी महिला को महीने के तीन दिन अछूत माना जा सकता है और चौथे दिन उसे इस श्रेणी से बाहर रखा जाए, ऐसा कानून या न्यायिक दृष्टिकोण संविधानिक रूप से सही नहीं है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तब की, जब भारत के सॉलिसिटर जनरलतुषार मेहता ने 2018 के सबरीमाला फैसले में किए गए उस कथन की आलोचना की, जिसमें 10-50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना अछूतता का रूप बताया गया था। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी रूप में अछूतता का अभ्यास निषिद्ध है। सबरीमाला मामले में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसले में कहा गया था कि महिलाओं को मासिक धर्म के आधार पर प्रवेश से रोकना अछूतता का रूप है और इसे अनुच्छेद 17 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा सबरीमाला मामले में एक राय है कि अनुच्छेद 17 महिलाओं पर लागू होता है आप उन्हें अछूत मान रहे हैं मुझे इस पर कड़ा आपत्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पश्चिमी देशों की तरह इतना पितृसत्तात्मक या लिंग आधारित पूर्वाग्रह वाला देश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले में पक्षकारों के वकीलों से कहा है कि वे निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करें। पीठ ने स्पष्ट किया कि और भी कई संवेदनशील मामले लंबित हैं, इसलिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। पीठ ने यह निर्देश सुनवाई के दौरान दिया और सभी पक्षों को समयबद्ध तरीके से अपने तर्क और दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि कोर्ट इस मामले में तेजी से फैसला सुनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धार्मिक स्वतंत्रता और उससे जुड़े संवैधानिक अधिकारों को लेकर सात महत्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन हैं। इन सवालों के जरिए संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या तथा उनकी सीमाओं को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले के लिए गठित पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ए.जी. मसीह, प्रसन्न बी. वराले, आर. महादेवन और जोयमाल्या बागची शामिल हैं। इस फैसले में महिलाओं को सभी आयु वर्ग के लिए सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। साथ ही इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जो धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। सबरीमाला मामले के अलावा, शीर्ष अदालत अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से संबंधित व्यापक संवैधानिक सवालों की भी जांच करेगी। इसमें मस्जिदों और दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश, अंतरधार्मिक विवाह के बाद पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, बहिष्कृत करने की प्रथाओं की वैधता और दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला जननांग विकृति की कानूनी वैधता जैसे मुद्दे शामिल हैं।

## मणिपुर के बिष्णुपुर में बम धमाका- दो बच्चों की मौत, दो महिलाएं घायल; पांच जिलों में 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद

इंफाल ।

मणिपुर में एक बार फिर हिंसक घटना सामने आई है। मंगलवार देर रात बिष्णुपुर जिले के मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा किए गए बम हमले में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामले को लेकर मृतक बच्चों के दादा ओइनम बाबूतोम ने बताया कि यह घटना रात करीब एक बजे हुआ। उस समय एक बम सीधे उनके घर पर आकर गिरा। घर के कमरे में उनकी बहू और दो छोटे बच्चे सो रहे थे। धमाका इतना जोरदार था कि पांच साल के मासूम और छह महीने की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों की मां इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए मणिपुर सरकार ने इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकार के निर्देश के अनुसार यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला एहतियातन लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलने से रोका जा सके।

**जातीय हिंसा की चपेट में रहा है मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाका**

जिस मोइरांग ट्रोंग्लाओबी इलाके में यह हमला हुआ, वह निचले क्षेत्र में आता है और चुराचांदपुर के पहाड़ी इलाकों के काफी करीब है। यह इलाका पहले भी 2023 और 2024 में जातीय हिंसा के दौरान लगातार गोलीबारी और तनाव का केंद्र रहा है।

**भाजपा विधायक ने की हमले की निंदा**

इस घटना के बाद स्थानीय भाजपा विधायक टीएच शांति सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे बेहद क्रूर और अमानवीय कृत्य बताया। विधायक ने कहा कि यह हमला आतंकवाद से कम नहीं है और समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इतने छोटे और मासूम बच्चों की इस तरह हत्या होना बेहद दुखद और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

## 91 लाख वोटर हटाने पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- सबसे अधिक वोट मुस्लिम और मतुआ के लोगों के नाम हटा दिए गए

बंगाल। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीति काफी गर्म है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की है.

उन्होंने कहा है कि हम उन सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं, जिनके नाम चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के चकदाहा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से मतुआ और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम हटा दिए गए हैं.

उन्होंने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस उन सभी लोगों के साथ खड़ी रहेगी, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. हम ट्रिब्यूनल्स में इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे.' मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा, 'पश्चिम बंगाल में मतुआ, राजबंशी और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को निशाना बनाकर विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जा रहे थे.' चुनाव आयोग के नए डेटा के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में से एसआईआर प्रक्रिया के बाद करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. वहीं, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके हस्तक्षेप के बाद विचाराधीन करीब 60 लाख मामलों में से लगभग 32 लाख नाम बहाल कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम और मतुआ समुदाय के लोगों के कटा है. 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाना निर्धारित किया गया है. पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल, 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल, 2026 को होगा. इसके बाद वोटों की गिनती और चुनाव के नतीजों के घोषणा 4 मई, 2026 को की जाएगी.

## कांग्रेस 70 से अधिक सीटें जीतेगी; सीएम हिमंत को बताया देश में सबसे भ्रष्ट- खरगे

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरमा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उनसे ज्यादा अहंकारी और घमंडी कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। खरगे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केवल अपने परिवार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और चाय, कोयला व जमीन से जुड़े सिंडिकेट चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मांग की कि हिमंत सरमा की पत्नी के कथित विदेशी संपत्तियों और तीन देशों के पासपोर्ट रखने के आरोपों की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि इन गंभीर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। चुनावी दावों को लेकर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में 72-73 सीटें जीतकर सरकार बनाएगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि उन्हें गांधी परिवार पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। असम में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जिससे सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है।

## लश्कर-ए-तैयबा नेटवर्क का भंडाफोड़, दो पाकिस्तानी आतंकियों समेत पांच गिरफ्तार

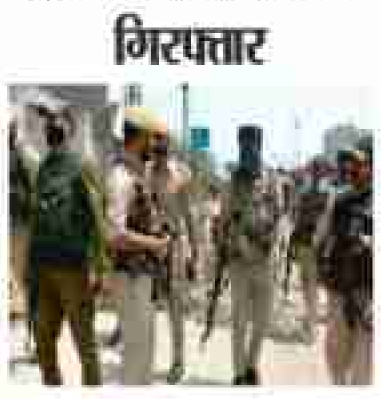

श्रीनगर । श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में दो पाकिस्तानी आतंकियों सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक सुनियोजित अभियान के तहत राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में कुल 19 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस को मॉड्यूल से जुड़े कई आपत्तिजनक और महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद हुए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

## पाताल से ढूंढ़ निकालेंगे, राहुल तक जाएगा केस- हिमंत की पवन खेड़ा को चुनौती, पत्नी पर आरोपों से भड़के सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर आ गई है। मुख्यमंत्री सरमा ने अपनी पत्नी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर पवन खेड़ा को दो टूक चेतावनी दी है। सरमा ने कहा कि अगर खेड़ा पाताल में भी जाकर छिप जाते हैं, तो असम पुलिस उन्हें वहां से भी ढूंढ कर लाएगी। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां के खिलाफ कुछ दस्तावेज भी पेश किए। मुख्यमंत्री का दावा है कि खेड़ा ने यह सब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर किया है। सरमा ने कहा कि पवन खेड़ा ने जो कागज पेश किए हैं, वे केवल राजनीति से प्रेरित हैं और इसके पीछे की असली पटकथा राहुल गांधी ने लिखी है।

**असम पुलिस की दिल्ली में दस्तक**

मुख्यमंत्री की चेतावनी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। मंगलवार यानी 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक टीम अचानक पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई ने असम से लेकर

दिल्ली तक, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सरमा ने कहा कि पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा, यानी, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इस बयान से साफ है कि असम सरकार इस मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री सरमा ने केवल पवन खेड़ा पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी इस मामले में घसीटा है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में राहुल गांधी से भी इस संबंध में कड़ी पूछताछ की जा सकती है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी अब अपने चरम पर है।

### जयराम रमेश, बोले- हिमंता बिस्वा परेशान और डरे हुए हैं

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें परेशान, हताश और डरा हुआ बताया। यह घटना तब हुई जब असम पुलिस की एक टीम ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास का दौरा किया। पुलिस की यह कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल पासपोर्ट विवाद से संबंधित है, जो मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की एफआईआर के बाद सामने आया है। एक्स से बात करते हुए रमेश ने निजामुद्दीन पूर्व स्थित खेड़ा के घर के बाहर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की निंदा की और इसे चुड़ैल का शिकार और दंभिक द्वारा राज्य मशीनरी का उपयोग करके विपक्ष की उन आवाजों को दबाने का प्रयास बताया जो कथित कुकर्मों को उजागर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और भयभीत हैं। यह कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जिसमें एक तानाशाह विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ रहा है।

## 50 करोड़ रुपये की लागत से नहर का जीर्णोद्धार, सरकार ने दी मंजूरी

कुरुक्षेत्र ।

हरियाणा और पंजाब के विवाद के बीच लंबे समय से उपेक्षित एसवाईएल नहर अब अपने मूल स्वरूप में लौटने जा रही है। करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से नहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे यह दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली की प्यास बुझाने में कारगर साबित होगी। सिंचाई विभाग ने बताया कि नहर के कायाकल्प का काम तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

SYL नहर के जीर्णोद्धार के बाद जरूरत पड़ने पर नरवाना ब्रांच नहर और मारकंडा नदी के पानी को भी छोड़ा जा सकेगा। इससे न केवल मारकंडा नदी से आने वाली बाढ़ का खतरा टलेगा, बल्कि नहर का सही उपयोग भी सुनिश्चित होगा।

**नहर की लंबाई और परियोजना की तैयारी**

कुरुक्षेत्र जिले में एसवाईएल नहर की लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है। जनवरी महीने में सिंचाई विभाग ने परियोजना को प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा था, जिसे तकनीकी टीम ने पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंचने के बावजूद पंजाब से अभी तक नहर में पानी नहीं मिल पाया है।

**सरकार से मिली मंजूरी, जल्द होगा कार्य शुरू**

एसवाईएल नहर परियोजना के बारे में एक्सईएन सिंचाई विभाग मुनीष बब्बर ने बताया कि सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही परियोजना पूरी कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

**पानी की उपलब्धता का लक्ष्य**

सिंचाई विभाग ने नहर के जीर्णोद्धार के बाद 10 हजार क्यूसेक पानी दक्षिणी हरियाणा तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसमें एसवाईएल नहर के माध्यम से 6,500 क्यूसेक और नरवाना ब्रांच के माध्यम से 3,500 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहली बार है जब नहरों का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

# यूएनएससी में अमेरिका को बड़ा झटका - ईरान के समर्थन में खुलकर आए रूस और चीन, होर्मुज को खोलने के प्रस्ताव पर किया वीटो

न्यूयॉर्क । पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच मंगलवार को अमेरिका को झटका लगा है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस और चीन ने उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसका मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना था। यह प्रस्ताव ऐसे समय में पारित नहीं हो सका, जब ईरान से समझौते के लिए अमेरिका की समय सीमा नजदीक आ रही है। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

**प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष में कितने वोट पड़े?**

सुरक्षा परिषद के 15 में से 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। पाकिस्तान और कोलंबिया ने मतदान से दूरी बनाई। जरूरी नौ वोट मिल गए थे। फिर भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं। उनके पास वीटो शक्ति है। इसी का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को रोक दिया गया। शुरुआत में प्रस्ताव में अनुच्छेद 7 शामिल था। इससे सदस्य देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए बल प्रयोग की अनुमति मिल सकती थी। रूस और चीन इसका विरोध कर रहे थे। इसी वजह से लंबे समय तक बातचीत चली। प्रस्ताव की भाषा बदली गई। अंत में जो प्रस्ताव लाया गया, उसमें केवल देशों से रक्षात्मक तरीके से सहयोग करने की बात कही गई।

बल प्रयोग की बात हटा दी गई थी। बहरीन को उम्मीद थी कि रूस और चीन कम से कम मतदान से दूरी बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर बंटी हुई नजर आई। रूस और चीन ने वीटो कर साफ कर दिया कि वे ईरान के साथ खड़े हैं। दोनों देशों का कहना है कि प्रस्ताव में ईरान की बहुत कड़ी आलोचना की गई थी।

**बहरीन ने यूएनएससी में क्या कहा?**

बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने यूएनएससी में कहा कि ईरान को होर्मुजल जलडमरूमध्य बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव खाड़ी क्षेत्र के इस अहम जलमार्ग के गंभीर हालात को देखते हुए लाया गया है। दुनिया के तेल और गैस का करीब एक-पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग

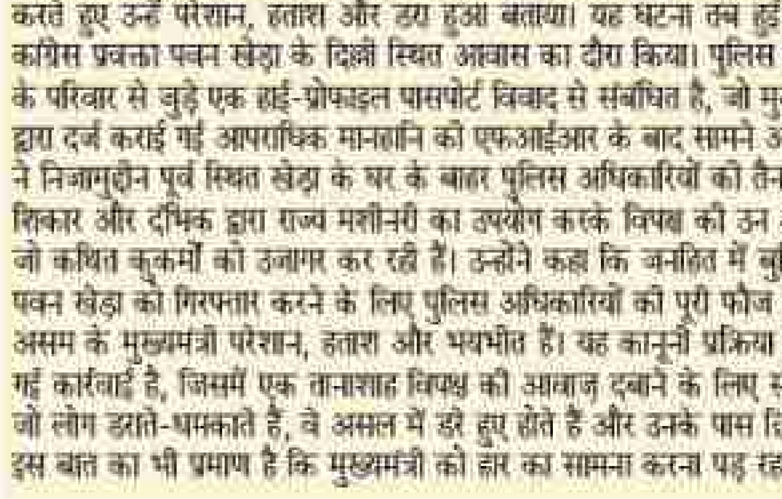

परिषद (जीसीसी) के देश वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा स्रोत हैं। इसलिए होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अल जयानी ने साफ कहा, ईरान को इस जलमार्ग को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। न ही वह दुनिया के लोगों को जरूरी ऊर्जा संसाधनों से वंचित कर सकता है।

**आज रात पूरी सभ्यता मिटा दी जाएगी, राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी**

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर ईरान को खौफनाक धमकी दी है। उन्होंने कहा कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।

मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि, अब जब हमारे सामने पूरी तरह सत्ता परिवर्तन की स्थिति है, जहां, अलग, अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग सत्ता में हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत घटित हो सकता है, कौन जाने? उन्होंने कहा, आज रात हमें विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम क्षणों में से एक का पता चल जाएगा। 47 वर्षों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौतों का आखिरकार अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो।

## अमेरिका-इजराइल ने ईरान के 3 पुल उड़ाए, कई मौतें व ट्रेन सेवाएं बंद

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तय समय-सीमा खत्म होने से पहले ही ईरान में कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कम से कम तीन बड़े पुलों को निशाना बनाकर उड़ा दिया गया है। उत्तर-पश्चिम ईरान के तबरेज-जांजन हाईवे पर बने एक अहम पुल को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। वहीं काशान में एक रेलवे पुल पर हमले में दो लोगों की मौत और तीन के घायल होने की खबर है।मशहद में हालात को देखते हुए ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि रेलवे नेटवर्क पर हमले की आशंका जताई गई थी। इसके अलावा तेहरान, कोम और लोरेस्तान समेत कई इलाकों में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट और एक

बिजली संयंत्र को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। रणनीतिक रूप से अहम खार्ग द्वीप पर भी दोबारा हमला हुआ है, जहां से तेल निर्यात किया जाता है। वहां हमले के बाद धुएं के गुबार उठते देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पारचिन कॉम्प्लेक्स जो मिसाइल और रक्षा उत्पादन से जुड़ा एक संवेदनशील सैन्य ठिकाना है वहां भी बड़ा धमाका हुआ है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, उत्तरी अल्बोर्ज प्रांत में हवाई हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। इजराइल की सेना का दावा है कि हाल के हमलों में 130 से अधिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं, जिससे ईरान की रक्षा क्षमता को बड़ा झटका लगा है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दिया हुआ है। चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के पुलों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाएगा जो अब होता दिख रहा है। इस बीच, ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से अपील की है कि वे अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल न करने दें।